EDITORIAL

Tasks before NEC

The NEC will meet at Delhi from july 13th to 14th as per the notified agenda. The review on election result at gross root level and find way sand means of organizational improvement will be the top priority. Strengthening our work at Branch/District level and improving paid membership by organized method should be materialized.

Protecting the company's viability, and Employees pension, job security against the 55(II) b, securing HRA on 78-2%, SC/ST concession on NEPP, Stagnation and fight against the decision of formation of Tower corporation, merger of MTNL to save employees from onslaught of the Govt. Policies, and the adverse effects on staff by the formation of business areas are some of our priority issues.

The Right of Bonus should be restored and bonus to be paid to our employees by resuming the discussion with the management.

Regarding wage revision, The government has appointed 3rd Pay Revision Committee (3rd PRC) headed by Retired Justice Satish Chandra to review and revise the existing structure of salary and emoluments of CPSE executives. The 3rd PRC will give its report in six months and the government decision on the recommendations of the Committee will effect from January 1, 2017.

This raised the hopes of our employees for the revision of wage, which is going to be last pay revision for majority employees absorbed. So it is necessary to revise the pension along with wage revision. It is pertinent to mention that the DOT Secretary assured that he will make Special reference to Wage revision committee for the revision of pension and that assurance need to be insisted. Last time the 7th wage negotiation for the non-executives notified earlier before the 2nd PRC. But this time the 3rd PRC notified by the Govt of India, but no pressure from PSU unions for next round of wage negotiations. Our first task should be to demand DPE to issue guidelines for 8th Round of Talks. Second task is to pressure BSNL management to constitute proper Bilateral Wage negotiating Body-again underline Bilateral not mere Officers committee - CMD should constitute Bilateral committee of both Officers and Unions. Third task is both Recognised Unions should ensure that the Bilateral body is a broad representative body for most of our Non Executive Unions. Fourth task is that we should move every step with broader consensus.

The demand of Up-gradation of Pay Scales for Executives was accepted by the management. Denial of the same to Gr D/RM is unfair. We have to demand for upgradation of all our lower grade employees to group 'C' level.

The CG employees are in war path from 11th july 2016 for the improvement in 7th CPC recommendations. This also have a major impact on our demand and settlement of wage structure as mentioned in the Terms of reference of 3rd PRC.

The major Central Trade unions have given a call for fighting out the anti labour policies of the present Government, on 2nd September 2016. It is our duty to be part of the mainstream struggle. Let us meet at New Delhi to steer our course of action.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दायित्व

अधिसूचित एजेन्डा के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13 एवं 14 जुलाई को होगी। हम उच्च प्राथमिकता के आधार पर सजमीं पर संगठन को मजबूत करने की पहल सहित विगत चुनाव के संबंध में गहन विचार करेंगे। संगठित होकर सदस्यता वृद्धि करने सहित शाखा/जिला स्तर पर अपने कार्य मजबूत करने के तरीकों पर विचार करेंगे।

कम्पनी की आर्थिक जीवंतता, कर्मचारियों का पेंशन, नौकरी की सुरक्षा, नियम 55 II बी का विरोध, 78.2 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर मकान किराये भत्ते का भुगतान एनईपीपी में एस सी/एस टी कर्मियों के लिए छूट स्टैगनेशन, टावर कम्पनी तथा एमटीएनएल के साथ विलयन, बिजनेस एरिया के गठन का कर्मचारियों पर प्रतिकुल प्रभाव आदि हमारे प्राथमिकता आधारित मुद्दे हैं।

बोनस के अधिकार की बहाली तथा प्रबंधन से वार्ता कर बोनस का भुगतान करना भी हमारे लक्ष्य में शामिल है।

वेतन पुननिरीक्षण, सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायधीश श्री सतीश चंद्र जी की नेतृत्व में अध्किारी वर्ग के लाये तृतीय वेतन पुननिरीक्षण समिति का गठन कर दिया है। यह समिति छः माह में अपनी अनुशंसा सौंपेगी तथा इस पर सरकार द्वारा निर्णय के उपरान्त यह 1 जनवरी 2017 से लागू किया जायेगा।

इससे हमारे कर्मचारियों की आशाएं जागृत हो गई हैं क्योंकि बीएसएनएल में शामिल बहुसंख्या कर्मियों के लिए यह अंतिम वेतन पुननिरीक्षण होगी अतएवं वेतन पुनर्निधारण के साथ पेंशन की पुननिरीक्षण एवं पुननिरीक्षण होना आवश्यक है। याद दिलाना आवश्यक है कि सचिव, दूरसंचार ने आश्वासन दिया था कि वेतन पुननिरीक्षण के समय विशेष संदर्भ के द्वारा इस मुद्दे का उठाया जायेगा।

पिछले समय द्वितीय वेतन पुननिरीक्षण से पूर्व वेतन समझौता हेतु सातवें दौर की वार्ता बुलाई गई थी लेकिन इस बार तृतीय वेतन पुननिरीक्षण के पूर्व अगली वार्ता के लिए किसी भी लोक उपक्रम के श्रमिक संगठनों ने आवाज नहीं उठाई। लोक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) से आठवें दौर की वेतन समझौता की मांगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी द्वितीय प्राथमिकता बीएसएनएल प्रबंधन पर दवाब बनाते हुए एक सापेक्ष द्वितीय वेतन समझौता समिति गठित करना। यह समिति नाम के लिए नहीं अपितु पूर्ण रूप से अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन को शामिल करते हुए सशक्त समिति गठित होनी चाहिए। हमारी तीसरी प्राथमिकता सभी नॉन एक्जीक्यूटिव यूनियन के साथियों को शामिल करते हुए व्यापक समिति गठित करने का प्रयास दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा करने का प्रयास दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा करनी होगी एवं हमारी चौथी प्राथमिकता होगी हर कदम पर सभी संगठनों की व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ना।

एक्जीक्यूटिव कर्मियों की वेतन वृद्धि की मांग को प्रबंधन ने स्वीकृति दे दी है वहीं ग्रप डी/आर.एम (सहायक तकनीकी सहायक) के वेतन उत्थान की मांग ठुकरा दी है। हमें एक जुट, होकर उस समूह का ग्रूप सी की स्तर के वेतन मांग सुनिश्चित करनी होगी।

सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 11 जुलाई 2016 से सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों में सुधार के लिए जंगे मैदान में उतर रहे हैं। जैसा कि लोक उपक्रम के लिए आहूत तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति के संदर्भ में वर्णित है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव तृतीय पी.आर.सी.पर भी होगा।

बहुसंख्यक केन्द्रीय श्रमिक संघों ने वर्तमान केंद्र सरकार के श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक लड़ाई का शंखनाद किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम श्रमिक समुदाय की मुख्यधारा के साथ चलें।

आइये दिल्ली में हम मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे।